MR. SPEAKER: The Prime Minister has got the right to inform the people and know their reaction.

13.29 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

REPORTED DEATH OF A HARIJAN SATYAGRAHI IN ALIGARH JAIL

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : नियम 377 के अधीन मैं सार्वजनिक महत्व का एक विषय यहां उठाना चाहता हूं।

सदन को ज्ञात है की हरियाणा के हरिजन दिल्ली में पिछले महीने से राज्य सरकार की हरिजन विरोधी नीति के विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जो जमीन 19 साल पहले उन्हें दी गई थी उस जमीन से वे बेदखल कर दिये गये हैं, उनकी खड़ी हुई फसल काट दी गई है और 25 हजार हरिजनों के परिवार हरियाणा में बेघर-बार हो गए हैं। यह आन्दोलन दिल्ली में हो रहा है। अभी तक 14 हजार हरिजन अपने को गिरफ्तारी के लिये पेश कर चुके हैं, 4 हजार हरिजन बंधु अभी तक जेलों में हैं जिन में औरतें भी हैं और बच्चे भी हैं। 12 नवम्बर को उनके ऊपर यहां लाठीचार्ज भी किया गया था।

इसी आन्दोलन में एक दुखदायी घटना गई है। जो हरिजन बंधु दिल्ली में पकड़े जाते हैं, उन्हें दिल्ली जेल में जगह न होने के कारण आस पासके प्रदेशों की जेलों में भेज जा रहे हैं। इसी तरह के एक सत्याग्रही, श्री जीग्रो राम अलीगढ़ की जेल में भेजे गये थे और 10 तारीख को जेल में ही उनका देहावसान हो गया।

अलीगढ़ के जेल अधिकारियों ने सत्याग्रही के परिवार वालों को बीमारी की कोई खबर नहीं दी। यहां तक कि मरने के बाद सत्याग्रही की लाश भी घर वालों को नहीं दी गई। सत्याग्रही को जेल में अग्नि के सुपुर्द कर दिया गया और परिवार वालों को उस सत्याग्रही की राख जेल के अधिकारियों से लेकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली।

अध्यक्ष महोदय, सत्याग्रही हरियाणा के है, गिरफ्तार दिल्ली में हो रहे हैं, उनकी मृत्यु अलीगढ़ की जेल में हो रही है। मैं आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं कि यह मामला कहां उठाया जाय? उत्तर प्रदेश में अगर यह मामला उठाया जाय तो कहा जायगा कि वह हरियाणा के सत्याग्रही थे। हरियाणा में उठाया जाय तो कहा जायेगा कि उसकी मृत्यु अलीगढ़ जेल में हुई इसलिये हरियाणा सरकार कुछ नहीं कर सकती। आखिर 14,000 हरिजन जेल में गये हैं, वह जमीन से बेदखल किये गये हैं, यह संसद अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हम सारी घटना पर मूक दर्शक नहीं रह सकते।

जब कभी इस सदन में चर्चा होती है डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स की तो मंत्री महोदय दावा करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स फंडामेंटल राइटस से भी ऊपर हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 46वें डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के अन्तर्गत यह कहा गया है कि शेड्यूल्स कास्टस और शेड्यूल्स ट्राइब्स के एजूकेशन और इकोनोमिक इंटरेस्ट को यह सरकार देखेगी। आप गृह मंत्री को कहें कि हरियाणा के हरिजन जो आन्दोलन कर रहें हैं, और जिन परिस्थितियों में अलीगढ़ में एक सत्याग्रही की मृत्यु हुई है उसके बारे में सदन में वक्तव्य दें। हरिजन नेता मांग कर रहे हैं कि मृत्यु के कारणों की अदालती जांच होनी चाहिये, और मैं चाहूंगा केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को कहे कि इस मामले की अदालती जांच करे, और केन्द्र सरकार हरियाणा की सरकार को भी कहे कि सारे मामले को शान्तिपूर्ण तरीके से निपटाये, और जिन हरिजनों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया है उन्हें उनकी जमीन पर फिर से बसाया जाय।

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North-East): He had given an adjournment motion.

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं ने एडजर्नमेंन्ट मोशन दिया था।

13.32 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Thirty minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at thirty-five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION RE: REPORTS OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1970-71 AND 1971-72—*contd.*

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, yesterday I referred to various procedures which ultimately resulted in the low priorities given to U.G.C. and the higher education .

How anxious the Government is towards the welfare of teachers. I framed questions and in reply to one of them the hon. Minister for Education answered on the 23rd July, 1973 in this House that the recommendations of the U.G.C. in their report on the Sen Committee in regard to the scales of pay of teachers in the universities and colleges are being examined by Government. Almost a similar question was answered by him on the 19th November, 1973 which contained 34 words. The earlier answer contained 36 words. So, the only progress made by them for the welfare of teachers is reduction in the number of words in the answer given by two words in these four months. So, this shows how anxious our Government is to ameliorate the conditions of the teachers as a whole. The Central Government employees are reacting to the proposals of the Pay Commission, the recommendations and all that and the decision of the Government thereon. The teachers are still unaware of what the proposals are and what the Government wants to do about it. I would only request the hon. Minister for Education, he being a teacher himself, to implement and expedite the sanction of the new scales—implementation of the new scales—for which the university and college teachers all over the country are looking forward because the same would be followed by the State Governments and the State Universities. But, here if nothing is done in the Centre, nothing will happen in the States.

Secondly I want to refer to the competition that goes on developing between two sets of Universities—the State Universities and the Central Unievrsities. At the moment, there are five Central Universities and one more is coming up in the North—Eastern Hill region giving a total of 6. According to an answer given to a question, recently, two more universities are going to come up. So, eight Central Universities and a large number of universities will, of course, continue to be in the State List or, what you may call, on the States side. These universities have been set up as a result of enactments in the State Legislatures.

It would be worthwhile to examine one thing. I suggest to the hon. Minister for Education to set up a Committee in the U.G.C. to find out the expenditure per head in the case of a student in the State University and in the Central University. It should not be confined only to the city but also to the backward and hill areas as well when they are getting more grants from Government and that is not spent on them. Rather I think that if there is any justification for establishing Central Universities, they should be located only in backward areas or in hill areas where the States cannot set up their universities.

With the rise in prices, it has become increasingly difficult for the construction of buildings in places where the communications are very